बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 226 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 09 सितम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू पर रिश्तेदारों को ठेका देने का आरोप, कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम सुनवाई में केंद्र सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से जुड़ा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी ठेके अपने परिवारजनों को दिए। यह याचिका गैर सरकारी संगठनों सेव मॉन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार सभी ठेके मुख्यमंत्री खांडू के करीबी रिश्तेदारों को दे रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केंद्र का पक्ष भी जरूरी है और गृह मंत्रालय व वित्त मंत्रालय को विस्तृत हलफनामा दाखिल करना चाहिए।

ये जो है जिंदगी! लौट गई यमुना, पीछे छोड़ गई जख्म... जरा हाल-ए-दिल्ली देखिए

नई दिल्ली । जब तक जान है, जिंदगी नहीं रुकती. उतरती यमुना की कीचड़ हो या जीवन की चुनौतियां, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है. राजधानी में यमुना का पानी उतर रहा है. लेकिन पीछे छोड़ गया है गाद, गंदगी और कीचड़ का ऐसा दर्द, जिसमें फंसकर लोगों की आह और कराह निकल रही है. यमुना का रौद्र रूप शांत होने के बाद लोग अब नई उम्मीद के सहारे, जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं. खरीदारों की चहल-पहल से गुलजार रहने वाला मोनेस्ट्री तिब्बती मार्केट अब भी आधा पानी डूबा है. अधिकतर दुकानें बंद हैं. बाढ़ की आहट मिलते ही लोगों ने दुकानों का सामान शिफ्ट कर दिया था, इसलिए नुकसान से बच गए. अब लोग पानी निकालने के लिए खुद ही जुट गए हैं. मोटर पंप, छोटी मशीनों के अलावा हाथों से गाद निकालने का काम किया जा रहा है. यमुना के आसपास की कई कॉलोनियों में हालत अब भी बदतर हैं. यमुना का प्रचंड रूप शांत हो रहा है, लेकिन उसका दर्द अब भी लोगों की जिंदगी को जकड़े हुए है. घरों, गलियों और रास्तों पर इसके निशान अब साफ नजर आ रहे हैं. कहीं पानी तो कहीं गाद और कीचड़ अटी पड़ी है. सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं क्योंकि पानी की निकासी के लिए जगह नहीं है. यमुना बाजार के घाटों के हाल भी बदहाल हैं. बाढ़ का पानी घरों में बदबूदार कीचड़ छोड़कर वापस लौट चुका है. हालात ये हैं कि पैदल चलना भी दूभर है. हर जगह कीचड़ और गाद ही गाद है. लेकिन स्थानीय लोगों की हिम्मत देखने लायक है. कमर तक सने होने के बावजूद इस आपदा से निजात पाने के लिए उन्होंने जी-जान एक कर दी है. सफाई का काम शिफ्टों में चल रहा है. यमुना के उफनाने के बाद आसपास की कॉलोनियों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया, लेकिन मुश्किलों के साथ ही सही, जिंदगी यहां भी बदस्तूर चलती रही. कीचड़ में लिपटी नन्ही बच्ची का जन्मदिन हो या फिर खाना पकाना-खाना, रिलीफ कैंप में रहते हुए भी लोगों ने जिंदगी के हर लम्हे को जिया. दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर सोमवार सुबह 7 बजे खतरे के निशान से नीचे 205.22 मीटर पर दर्ज किया गया. एक दिन पहले, रविवार रात 9 बजे जलस्तर 205.33 मीटर था. गुरुवार को यहां वॉटर लेवल 207.48 मीटर तक पहुंच गया था, जो इस मौसम का सबसे उच्चतम स्तर था. इसके बाद से जलस्तर में गिरावट आ रही है। सोमवार सुबह छह बजे जलस्तर 205.24 मीटर दर्ज किया गया। राजधानी के लिए चेतावनी का निशान 204.50 मीटर और खतरे का निशान 205.33 मीटर है. जलस्तर 206 मीटर पर पहुंचने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम शुरू कर दिया जाता है.

किसान के दर्द पर खड़गे का अपमान! भाजपा ने साधा निशाना, बोली- यही कांग्रेस की मानसिकता

नई दिल्ली । भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर किसानों के दर्द का मज़ाक उड़ाने के लिए तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की असंवेदनशीलता ने दशकों तक किसानों को निराशा में धकेला है। एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए, भाजपा नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अगली बार जब राहुल गांधी या कांग्रेस किसानों के लिए बोलने का दिखावा करें, तो उन्हें यह याद दिलाएँ - उनके अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों के दर्द का मज़ाक उड़ाया था और उनसे कहा था कि हर समय रोना-धोना और प्रचार की तलाश न करें। यह कांग्रेस की असंवेदनशीलता है जिसने दशकों तक किसानों को निराशा में धकेला। मालवीय ने किसानों की आय दोगुनी करने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक वास्तविक क्रांति की शुरुआत की - किसानों को विविधता लाने, उनकी आय दोगुनी करने, मौसमी जोखिमों से फसलों की रक्षा करने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में मदद की। कांग्रेस ने मज़ाक उड़ाया, प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया। इससे पहले आज, भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर किसानों का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब एक किसान खड़गे के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा था, तो उन्होंने उसका अपमान किया। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों और उनके हितों के खिलाफ है। पूनावाला ने एएनआई से कहा कि कांग्रेस किसानों, जवानों और भारत के संविधान का अपमान करती है... कल एक किसान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की और खड़गे जी ने उसे भाग जाने को कहा। यह किसानों के प्रति उनके रवैये को दर्शाता है। कांग्रेस ने 8 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू नहीं की। कर्नाटक में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं... कांग्रेस किसानों के खिलाफ है... बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक में, बाढ़ निरीक्षण के दौरान कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को पीठ पर उठाकर ले जाया गया। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों द्वारा कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को कंधों पर उठाकर ले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूनावाला ने उन पर भी निशाना साधा।

इसे अधिकार की भावना करार देते हुए, भाजपा नेता ने अनवर पर तीखा प्रहार करते हुए पूछा कि क्या उन्हें बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, पूनावाला ने लिखा, कांग्रेस की अधिकार की भावना। बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी वे वीवीआईपी प्रोटोकॉल चाहते हैं? खड़गे जी किसानों का अपमान करते हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बाढ़ राहत का मज़ाक उड़ाते हैं - बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए लोगों के कंधों पर बैठते हैं। कांग्रेस सांसद वीवीआईपी मोड में। राहुल गांधी छुट्टी मोड में। आप छिपने की स्थिति में। केवल प्रधानमंत्री मोदी काम करने की स्थिति में।

दिल्ली पुलिस अधिकारियों की फिजिकल उपस्थिति पर सर्कुलर जारी, अब वकीलों ने हड़ताल पर लिया ये फैसला

नई दिल्ली । दिल्ली में चल रही वकीलों की हड़ताल अब खत्म हो गई है. दरअसल, पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से एक लैटर जारी किया गया है, जिसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि सभी आपराधिक मामलों में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी अब गवाही/साक्ष्य के लिए माननीय कोर्ट के समक्ष फिजिकली रूप से उपस्थित होंगे. इस फैसले के बाद नई दिल्ली बार एसोसिएशन समन्वय समिति की आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वकीलों की प्रमुख मांग पूरी हो चुकी है. इसलिए हड़ताल का आह्वान तत्काल प्रभाव से वापस लिया जा रहा है. समिति ने इसे वकीलों की एक बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि अब न्यायिक प्रक्रिया और भी पारदर्शी और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकेगी. पुलिस मुख्यालय के आदेश 4 सितंबर को जारी किया था, उसमें संशोधन किया गया है. नए सर्कुलर में साफ कहा गया है कि अब वर्चुअल पेशी की जगह पुलिसकर्मियों को कोर्ट में जाकर गवाही देनी होगी. इस आदेश को पुलिस आयुक्त की मंजूरी मिल चुकी है. स्पेशल सीपी (क्राइम) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने सभी जिलों और इकाइयों के डीसीपी, साथ ही

स्पेशल/जॉइंट/एडिशनल सीपी को निर्देश भेज दिए हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट में वकीलों ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की उस अधिसूचना के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिसकर्मियों को थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अनुमति दी गई है. वकीलों का कहना है कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा है और अदालतों की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है. वकीलों का आरोप है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस गवाहों को अदालत से जोड़ने का निर्णय असल में न्याय को कमजोर करने की कोशिश है. उनके अनुसार, यदि पुलिसकर्मी कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे तो गवाह की विश्वसनीयता की जांच गंभीर रूप से प्रभावित होगी. प्रदर्शन के दौरान एक वकील ने कहा, गवाही कोर्ट में आमने-सामने होनी चाहिए. गवाह का आचरण, उसकी हिचकिचाहट और उसके जवाब देने का तरीका सब न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है. वीडियो पर यह सब पूरी तरह संभव नहीं है. उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि अदालत में पुलिस अधिकारियों की शारीरिक उपस्थिति से ही निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सकती है. यदि गवाह थाने से ही बोलेंगे तो क्या यह गारंटी है कि उन पर किसी का दबाव नहीं होगा? कोर्ट का माहौल अलग होता है और वहीं सचाई सामने आती है. वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही की व्यवस्था पुलिस को अनुचित लाभ पहुंचा सकती है. इससे गवाहों पर सीधा या अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ने का खतरा रहेगा. उनका कहना है कि यह अधिसूचना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चोट है और संविधान प्रदत्त निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करती है. राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में जुटे वकीलों ने नारेबाजी करते हुए मांग की कि इस अधिसूचना को तुरंत वापस लिया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आदेश को रद्द नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. विरोध कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि हम न्यायिक प्रक्रिया के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे. गवाह अदालत में ही पेश हों, यही परंपरा और यही कानून का तकाजा है. गौरतलब है कि उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से हाल ही में जारी अधिसूचना में कहा गया था कि पुलिसकर्मी थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों में गवाही दे सकते हैं. सरकार का तर्क है कि इससे पुलिसकर्मियों का समय बचेगा और लंबित मामलों की सुनवाई तेजी से हो सकेगी. लेकिन वकीलों का कहना है कि प्रशासनिक सुविधा की आड़ में न्याय की नींव को हिलाया जा रहा है.

अपने 75वें जन्मदिन पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू करेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि यह राष्ट्रव्यापी अभियान भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए आयोजित किया गया है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा तक बेहतर पहुँच प्रदान की जा सके और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाई जा सके, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ स्वास्थ्य सेवा अभी भी एक विशेषाधिकार है। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर शुरू किया जाने वाला यह कार्यक्रम, स्वस्थ भारत के निर्माण के सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। जेपी नड्डा के ट्विटर पोस्ट के अनुसार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के दौरान, सरकार पूरे भारत में लगभग 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगी। ये शिविर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में लगाए जाएँगे, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पहुँचेंगे। इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएँगी, जिनमें निवारक देखभाल, जाँच और उपचार शामिल हैं। चिकित्सा सेवाओं के अलावा, देश भर के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण माह भी मनाया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारत में परिवारों के समग्र कल्याण में सुधार के लिए पोषण जागरूकता, स्वस्थ आहार और जीवनशैली संबंधी आदतों को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। सरकार का मानना है कि जमीनी स्तर पर पोषण और जागरूकता स्वस्थ समुदायों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की सफलता लोगों की सामूहिक भागीदारी पर निर्भर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अन्य सभी हितधारकों से इस स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में आगे आकर सक्रिय योगदान देने की अपील की है। इस भागीदारी को जन भागीदारी अभियान कहा जा रहा है, क्योंकि यह कार्यक्रम भारत की ग्रामीण आबादी तक स्वास्थ्य सेवा की पहुँच बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करता है, जिसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

सीएम के पति सरकारी मीटिंग में, आप का हमला- दिल्ली बनी फुलेरा पंचायत, सुपर सीएम चला रहे राज! बीजेपी का पलटवार

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अपने पति को सरकारी कामों में शामिल होने की अनुमति देने का आरोप लगाया और प्रशासन की तुलना लोकप्रिय वेब सीरीज़ की काल्पनिक फुलेरा पंचायत से की। एक सरकारी बैठक की तस्वीर साझा करते हुए, जिसमें मुख्यमंत्री के पति मनीष गुप्ता उनके बगल में बैठे थे, आप ने कहा कि राजधानी को एक ग्राम पंचायत की तरह चलाया जा रहा है जहाँ गैर-निर्वाचित परिवार के सदस्य प्रभाव रखते हैं। दरअसल, रेखा गुप्ता ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया था। गुप्ता ने एक्स पोस्ट में बताया कि बैठक में अधिकारियों को क्षेत्र में चल रहे कार्यों की प्रगति का नियमित रूप से आकलन करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, पूर्ण और लंबित परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई और भूमि उपयोग से संबंधित विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।

रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता, जो शालीमार में एक व्यवसायी हैं, बैठक में देखे गए, जिससे हंगामा मच गया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि रेखा गुप्ता ने अपने पति को बैठक में क्यों आने दिया और इसकी तुलना काल्पनिक गाँव फुलेरा से की, जहाँ महिला प्रधान के पति का दबदबा है। भारद्वाज ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली सरकार फुलेरा पंचायत में तब्दील हो गई है। जैसे फुलेरा में महिला सरपंच का पति असली मुखिया की भूमिका में था, वैसे ही आज दिल्ली में मुख्यमंत्री के पति सरकारी बैठकों में बैठे नज़र आ रहे हैं। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। देश की राजधानी में लोकतंत्र और

संवैधानिक मर्यादाओं का इस तरह मज़ाक उड़ाया जा रहा है। भारद्वाज ने भाजपा पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अक्सर कांग्रेस पर वंशवादी राजनीति का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब उसी को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने लिखा, वंशवाद को लेकर कांग्रेस को कोसने का कोई मौका न गँवाने वाली भाजपा को जवाब देना चाहिए - अगर यह वंशवाद नहीं है, तो क्या है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की मुख्यमंत्री के पास एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिस पर वह भरोसा कर सकें? उनके पति को इस तरह सरकारी व्यवस्था का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है? आप नेता संजय सिंह ने भी इसी तरह की राय दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में दो मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं। उन्होंने कहा, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, उनके पति सुपर मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने छह महीने में दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। इस बीच, भाजपा ने आप के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि गुप्ता के पति के सरकारी बैठक में बैठने में कुछ भी गलत नहीं था। भाजपा के हरीश खुराना ने कहा कि सबसे पहले, मनीष गुप्ता न केवल रेखा गुप्ता के पति हैं, बल्कि वह शालीमार बाग के निर्वाचन क्षेत्र का भी काम देख रहे थे। उन्होंने कहा कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इसे देख रहे थे। उन्होंने लोगों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एक प्रतिनिधि के तौर पर, वह वहाँ बैठ सकते हैं। बैठक सिर्फ़ अधिकारियों के लिए नहीं थी। कुछ निवासी भी वहाँ बैठे थे। उन्होंने यह भी कहा कि आप इससे निराश है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधने के लिए कुछ और ठोस तरीका ढूँढ़ना चाहिए। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की समीक्षा बैठक कर रही थीं, जिसका प्रबंधन उनके पति करते हैं—ठीक वैसे ही जैसे श्रीमती शीला दीक्षित के निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन उनकी बहन रमा धवन करती थीं, और सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन देखती थीं। उन्होंने कहा, हालांकि, सुनीता केजरीवाल के विपरीत, मुख्यमंत्री के पति उनकी कुर्सी पर नहीं बैठे थे या कोई अवैध आदेश जारी नहीं कर रहे थे, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों को फाइल में दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया हो, जैसा कि मुख्यमंत्री महोदया ने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, रेखा गुप्ता को सिर्फ इसलिए निशाना बनाना बंद करें क्योंकि वह एक महिला हैं जो अच्छा काम कर रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ अरविंद केजरीवाल को और अधिक साधारण बना रही हैं।

मोदी को अब काले धन से परहेज़ नहीं !

अनिल जैन

भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी को अब काले धन से कोई परहेज नहीं है। पिछले दिनों अहमदाबाद में मारुति सुजुकी के हंसलपुर संयंत्र में पहले इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा, मेरी स्वदेशी की परिभाषा बहुत सरल है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि पैसा किसका है, चाहे वह डॉलर हो, पाउंड हो, या वह पैसा काला या गोरा हो। लेकिन उस पैसे से जो उत्पादन होता है, उसमें मेरे देशवासियों का पसीना होना चाहिए।'' गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जो प्रमुख मुद्दे उठाए थे उनमें एक मुद्दा काले धन का भी था। उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में कहा था कि अगर विदेशों में जमा भारतीयों का काला धन वापस भारत में आ जाए तो हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार बनी तो वे प्राथमिकता के आधार पर विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे और काले धन की अर्थव्यवस्था समाप्त होगी। हालांकि पिछले 11 साल में विदेशों में जमा भारतीयों का धन बढ़ गया है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि वह सब काला धन है, लेकिन अगर हो भी तो प्रधानमंत्री को उससे कोई मतलब नहीं। अब उनका नजरिया बदल चुका है। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि पैसा काला हो या गोरा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर काले धन के खिलाफ लड़ाई या ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों का क्या मतलब है?

कांग्रेस के शीर्ष नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कर्नाटक की बेंगलुरू सेंट्रल सीट के तहत आने वाली महादेवपुरा सीट पर वोटर लिस्ट में एक लाख से ज्यादा वोटों की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने राहुल से हलफनामा देकर शिकायत करने को कहा, लेकिन राहुल ने कोई हलफनामा नहीं दिया। अब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर हुई सभा में उन्होंने यह कह कर भाजपा नेताओं की नींद उड़ाई है कि वोट चोरी पर उनके पास %हाइड्रोजन बम' है, जो जल्दी ही फटेगा। अब भाजपा के नेता इस चिंता में है कि हाइड्रोजन बम में क्या हो सकता है? अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र या हरियाणा की किसी सीट का मामला होगा। लेकिन भाजपा में ही कुछ नेता यह कयास लगा रहे हैं कि कहीं राहुल वाराणसी सीट को लेकर तो कोई खुलासा नहीं करने वाले हैं? गौरतलब है कि राहुल ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ऐसा तभी होगा, जब वाराणसी की कोई पोल खुलेगी। गौरतलब है कि वाराणसी लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव में कई दौर की गिनती में प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय से पीछे चल रहे थे। अंत में मोदी डेढ़ लाख वोटों से जीते, जबकि 2019 के चुनाव में उनकी जीत करीब पांच लाख वोटों से हुई थी। इसीलिए राहुल के %हाइड्रोजन बम' में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है।

गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत पर मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए लाए गए तीन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजने के बाद विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियां इसके बहिष्कार की फैसला कर रही है और स्पीकर ओम बिरला के लिए जेपीसी का गठन मुश्किल हो गया है। स्पीकर ने सभी पार्टियों से जेपीसी के लिए सदस्यों के नाम मांगे हैं लेकिन किसी भी पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले में दूसरी विपक्षी पार्टियों की राय ले रही है। कांग्रेस की जो राय होगी उसके हिसाब से डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीएम आदि पार्टियां फैसला करेंगी। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पहले ही इसके बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से याद दिलाया गया है कि पहली बार विपक्षी पार्टियां किसी जेपीसी का बहिष्कार नहीं कर रही है। डेरेक ओ ब्रायन ने याद दिलाया कि बोफोर्स मामले की जांच के लिए जेपीसी बनी थी तो छह पार्टियों ने उसका बहिष्कार किया था। उसमें तेलुगू देशम पार्टी और असम गण परिषद भी शामिल थी, जो अब एनडीए में है। स्पीकर के सामने मुश्किल यह है कि इस बार विपक्ष की लगभग सभी पार्टियां एक गठबंधन में है। उनका फैसला एक राय से हो सकता है। पहले की तरह विपक्ष बिखरा होता तो मुश्किल नहीं होती। दूसरे विपक्षी गठबंधन से बाहर की पार्टियों के पास सांसद नहीं है। इसीलिए विपक्ष के फैसले का इंतजार हो रहा है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल के विवाद का असर कई जगह दिख रहा है। रिलायंस समूह का अमेरिका में होने वाला कार्यक्रम रद्द हो गया है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा में इसका असर दिखा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दोपक्षीय वार्ता के दौरान जयशंकर की जगह अजित डोवाल मौजूद थे। पुतिन के साथ उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव थे तो मोदी के साथ डोवाल मौजूद थे। बाद में मीडिया में भी यह प्रचार किया गया कि भारत की रणनीति बदल रही है और इसीलिए मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद थे। दरअसल यह प्रचार जयशंकर और डोवाल के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद से ध्यान हटाने के लिए चलाया गया।

गौरतलब है कि जयशंकर और डोवाल में पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। मीडिया की खबरों में बताया गया कि जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर अमेरिका में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ओआरएफ के प्रमुख है और आरोप है कि उन्होंने भारत की कई खुफिया जानकारियां अमेरिका को लीक की। मीडिया में यह नैरेटिव बना कि मोदी को उनके एक करीबी ने धोखा दिया है। इस विवाद के बीच रिलायंस समूह के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की ओर से अमेरिका में होने वाला एक हफ्ते का इंडिया वीक कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका से चल रहे विवाद और ऊपर से जयशंकर बनाम डोवाल के विवाद की वजह से कार्यक्रम टला है।

आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर जाने का फैसला हो गया है। बताया जा रहा है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में मोदी मणिपुर के दौरे पर जा सकते है। गौरतलब है कि मणिपुर में मई 2023 में जातीय हिंसा की शुरुआत हुई थी और करीब दो साल तक जारी रही, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग विस्थापित हुए, महिलाओं को नग्न करके सड़कों पर घुमाया गया, लोगों के मकान और सरकारी इमारतें जला दी गईं। जब दो साल तक हिंसा रोकी नहीं जा सकी तो भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को किसी तरह हटा कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया। हालांकि विधानसभा निलंबित रखी गई ताकि किसी समय सरकार बनाई जा सके। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद केंद्र सरकार ने पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को राज्यपाल बना कर भेजा। उनके जाने के बाद भी छिटपुट हिंसा होती रही लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगभग शांति है। गौरतलब है कि भाजपा और सरकार की ओर से बार-बार कहा जा रहा था कि शांति बहाली के बाद प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे। सो, कहा जा रहा है कि शांति बहाल हो गई है और इसलिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जरूर मणिपुर गए थे और हिंसा प्रभावित लोगों से मिले थे। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज होगी। मणिपुर में हटाए गए मुख्यमंत्री बीरेन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं।

अमेरिका के साथ भारत के टैरिफ विवाद से कॉरपोरेट बाबा रामदेव को मुंहमांगी मुराद मिल गई है। वे पिछले कई सालों से अपनी कंपनी पतंजलि के उत्पादों को स्वदेशी के नाम पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे वे खुलेआम धर्म के आधार पर विभाजन करवा कर भी अपना सामान बेचने की कोशिश कर चुके हैं, जिसके लिए उनको अदालत से फटकार मिली है। लेकिन अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बाद स्वदेशी को प्रमोट करने के नाम पर अपनी कंपनी के उत्पाद बेचने की उनकी मुराद पूरी होती दिख रही है। जैसे ही 27 अगस्त को अमेरिका का बढ़ाया हुआ अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लागू हुआ, रामदेव ने जोर-शोर से स्वदेशी का ढोल पीटना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी अपनाने की अपील से भी रामदेव के अभियान को फायदा हुआ। 27 अगस्त को तो रामदेव और उनकी पूरी टीम दिल्ली और नोएडा के टेलीविजन चैनलों के ठिकानों में घूम रही थी।

वे हर जगह इंटरव्यू दे रहे थे। भारत को सबसे बड़ा बाजार बता रहे थे। भारतीयों के स्वाभिमान को ललकार रहे थे और परोक्ष रूप से पतंजलि का सामान खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे थे। हालांकि उनके कई उत्पाद भी बाहर से मंगाए गए कंपोनेंट से बनते हैं। बहरहाल अपने भगवा चोले और स्वदेशी के प्रचार से वे इस स्थिति का सबसे ज्यादा लाभ उठाने की स्थिति में दिख रहे हैं। लेकिन वे यह भूल रहे है कि लोगों के लिए स्वदेशी के साथ-साथ उत्पादों की गुणवत्ता भी मायने रखती है।

सम्पादकीय...

कोई निशान नहीं छोड़ा

बाढ़ ने इस बार रैडक्लिफ द्वारा 78 वर्ष पूर्व खींची गई विभाजन रेखाओं को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। लगता था कि क्षुब्ध लहरें उस विभाजन को पूरी तरह नकार रही थीं। न कोई 'एलओसी' न कोई 'एलएसी'। आंधियों, तूफानों व बाढ़ों के अपने तौर-तरीके हैं। यदि 'लूटपाट' खून व सत्ता के प्यासे लोगों ने 78 वर्ष पहले अराजकता दिखाई थी तो आंधी, तूफान व बाढ़ क्यों न अराजक हो जाएं। हुसैनीवाला-सीमा फिरोजपुर व फाजिल्का-सीमा पर स्थित सादकी की 'रिट्रीट-सेरेमनी' वाले मंच भी बाढ़ ने इस बार बहा दिए। इस समय भारत-पाक के सैकड़ों गांवों के खेत बाढ़ के पानी में डूबे हैं। आज रैडक्लिफ जीवित होता तो 113 वर्ष का होता। अगर रूहें कब्रों के आसपास वाकई भटकती हैं तो रैडक्लिफ की रूह भी सिर धुनने पर विवश हो जाती। भारत-पाक सीमा के पार वे लगभग सभी गांव पानी में डूबे हैं जिनका प्रयोग आतंकी संगठन अपने प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और 'लांचिंग पैड' बनाने के लिए करते आ रहे थे। वहां 700 वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्र प्रभावित है और 33 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। रैडक्लिफ भारत विभाजन की विभीषिका का संभवत सर्वाधिक चर्चित व अभिशप्त पात्र था। उसके अंतिम दिन अच्छे नहीं बीते। वह सदैव उदास रहता। उसे यही लगता कि वह 'विश्व के सबसे बड़े महाप्रेशन' का अपराधी था। ये हादसों के दिन थे। पूरे घटनाक्रम की कमोबेश हर घटना हादसों की मानिंद घट रही थी। चारों तरफ विसंगतियां, विरोधाभास भरे पड़े थे। यह एक ऐतिहासिक विरोधाभास था कि जिस तारीख को पाकिस्तान अस्तित्व में आया, उस दिन तक उस देश की सीमाएं तय नहीं हो पाई थीं। लगभग साढ़े चार लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लगभग आठ करोड़ लोगों के लिए आवंटित किया जाना था। स्वतंत्र पाकिस्तान 14 अगस्त को अस्तित्व में आ गया था। 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहरा। मगर दोनों देशों के बीच सीमा रेखा एक दिन बाद 16 अगस्त को ही खींची जा सकी। यानि आजादी पहले मिल गई, सीमाएं बाद में तय हुईं। इन सीमा रेखाओं की निशानदेही जिस सीमा आयोग ने की, उसके अध्यक्ष एक आर्किटैक्ट सर सिरिल रैडक्लिफ थे। यह भी शायद उस काल की सबसे बड़ी विसंगति थी कि एक ऐसे शख्स को इस ऐतिहासिक निशानदेही का काम सौंपा गया जो इससे पहले एक पर्यटक के रूप में भी कभी भारत नहीं आया था। उसने यहां की संस्कृति, भूगोल, धर्म, जातियों के बारे में जो कुछ भी जाना यहां आकर जाना। अब थोड़ा पीछे लौटें। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 15 जुलाई, 1947 को 'इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947' पारित किया। इस कानून के तहत सिर्फ एक माह बाद अर्थात 15 अगस्त, 1947 को 'ब्रिटिश भारत के प्रांतों' को दो सार्वभौम प्रभुसत्ता सम्पन्न देशों के बीच विभाजित किया जाना था। एक का प्रस्तावित नाम 'यूनियन ऑफ इंडिया' और दूसरे का 'डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान' था। विभाजन से पहले भारत का लगभग 40 प्रतिशत भाग छोटे-बड़े राजाओं, महाराजाओं, नवाबों के अधिकार में था। कोई भी रेखा, सड़क तंत्र, रेल तंत्र, संचार तंत्र, सिंचाई तंत्र और बिजली तंत्र को तहस-नहस किए बिना मुमकिन नहीं थी। खेतों की स्थिति भी यही थी। मगर दलीलों, सामान्य बुद्धि और तकनीकी एवं ऐतिहासिक व भौगोलिक मजबूरियों को एक तरफ हाशिए पर सरका दिया गया। बस विभाजन रेखाएं खींच दी गईं। इस सारी कवायद के लिए दो सीमा आयोग गठित हुए थे। एक बंगाल के लिए और दूसरा पंजाब के लिए। दोनों का ही अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ को बनाया गया। रैडक्लिफ 8 जुलाई, 1947 को पहली बार भारत पहुंचे थे। उन्हें अपने समूचे कार्य के लिए 5 सप्ताह का नपा तुला समय दिया गया। दोनों आयोगों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दो-दो प्रतिनिधि शामिल थे लेकिन किसी नुक्ते पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद की स्थिति में अंतिम फैसला रैडक्लिफ का होता था। रैडक्लिफ को समय बेहद नाकाफी लग रहा था। मगर इस बारे में वायसराय, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के नेता अड़िग थे। वे समय सीमा को बढ़ाने के कतई पक्ष में नहीं थे। इस आयोग में रैडक्लिफ के अलावा शेष सभी सदस्य पेशे से वकील थे। जिन्ना व नेहरू का सम्बन्ध भी वकालत से ही था। किसी भी सदस्य के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था। कोई भी नहीं जानता था कि विभाजन सीमा कैसे तैयार होती है। रैडक्लिफ को सिर्फ इस बात की सन्तुष्टि थी कि उनका प्राइवेट सैक्रेटरी क्रिस्टोफर ब्यूमैंट पंजाब की हर स्थिति से पूरी तरह वाकिफ था। पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था व वहां की जिन्दगी के बारे में लगभग पूरी जानकारी उसे थी। अब इतिहासज्ञ व विशेषज्ञ इस बात को स्वीकारते हैं कि यदि थोड़ी सावधानी और सजगता से काम लिया जाता तो विभाजन की अकल्पनीय विभीषिका से बचा जा सकता था। ऐसे अनेक मंजर सामने आए जबकि किसी एक गांव को बीच में से बांटना पड़ा। एक गांव का कुछ भाग पाकिस्तान को मिला, शेष हिन्दुस्तान को। रैडक्लिफ घनी आबादी वाले क्षेत्रों के बीच विभाजक रेखा के हक में था। मगर इससे कई ऐसे घर भी बंटे जिनके कुछ कमरे भारत में गए, कुछ पाकिस्तान में। रैडक्लिफ बार-बार एक ही दलील देता 'हम कुछ भी कर लें लोग बर्बादी तो झेलेंगे ही।' रैडक्लिफ ने ऐसा क्यों कहा, यह शायद स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत छोड़ने से पहले उसने सारे नोट्स (अंतिम रपट के अलावा) नष्ट कर दिए थे ताकि बाद में विवादों के मुद्दे न उठें। वैसे भी उसे भारत की आबोहवा रास नहीं आ रही थी। वह जल्दी से जल्दी स्वदेश लौटना चाहता था। समूची विभाजक कार्यवाही यथासम्भव गुप्त रखी गई। अंतिम रपट (अवार्ड) 9 अगस्त, 1947 को तैयार हो गई थी, मगर उसे विभाजन से दो दिन बाद 17 अगस्त को ही सार्वजनिक किया गया। रैडक्लिफ की उम्र उस समय सिर्फ 48 वर्ष थी। उन दिनों 8 जुलाई, 1947 से लेकर 9 अगस्त तक उसने किसी भी सामाजिक समारोह या गतिविधि में शिरकत नहीं की। वह सिर्फ अपने काम में ही व्यस्त रहता। थोड़ी सी अवधि में बहुत बड़े काम को अन्जाम देना आसान नहीं था। ज्यादातर मुसलमान तब भी यही मानते थे कि पाकिस्तान बनने के बाद भी हिन्दुस्तान में आने जाने की सहूलियत कायम रहेगी।

अनेक समृद्ध मुसलमानों ने अपनी कई सम्पत्तियां बम्बई व दिल्ली में बदस्तूर बनाए रखीं। जिन्ना ने मालाबार हिल बम्बई (अब मुम्बई) स्थित अपनी कोठी बेची नहीं थी हालांकि दिल्ली वाली कोठी उन्होंने बेच दी थी। बम्बई से जिन्ना अनेक मामलों में जुड़े हुए थे। इनमें से एक कारण, अपनी बेगम रत्ती की स्मृतियां भी थीं। प्रॉपर्टी का बंटवारे में रैडक्लिफ व्यावहारिक मामलों में कोरा था। अपनी नियुक्ति से पहले उसने वेतन भत्तों, परिवार-खर्च, निःशुल्क यात्रा, निःशुल्क रहन-सहन जैसी छोटी-छोटी शर्तें भी अपनी सरकार से लिखित में मनवाईं। जाहिर है वह न तो राजनीतिज्ञ था, न ब्यूरोक्रेट।

राजनीति का नया हथियार : निजी अपमान

सुनील कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितम्बर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड' का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ में प्रधानमंत्री ने वही किया, जिसका डर था। प्रधानमंत्री ने एक सप्ताह पहले की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा- मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में आरजेडी-कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां-बहन-बेटी का अपमान है। प्रधानमंत्री 28 अगस्त 2025 को दरभंगा में घटी उस घटना का वर्णन कर रहे थे, जब सभा समाप्त होने के बाद एक पिकअप वैन चालक ने मंच पर चढ़कर प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे। इस ड्राइवर को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। प्रधानमंत्री हों या कोई आम व्यक्ति ह्र किसी को गाली देना, धमकाना, मारना-पीटना, या किसी के घर-दफ्तर में जबरन घुसने जैसे कृत्य सही नहीं ठहराए जा सकते। अफसोस की बात है कि भारत में झगड़े की शुरुआत हो या पुलिस की पूछताछ—अक्सर मां-बहनों की गाली से होती है। यहां तक कि बहुत नजदीकी जताने का तरीका हो या कुछ पेशेवर तबकों की बातचीत—वहां भी शुरुआत मां-बहन की गाली से ही होती है। संसद से लेकर सड़क और मीडिया की बहसों तक, हम नेताओं के मुंह से गालियां सुन चुके हैं। ऐसे में एक लेफ्ट ड्राइवर (जिस पर पुलिस पहले ही कार्रवाई कर रही है) की गाली को प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस कदर प्रमुखता देना, उनकी कमजोरी को दर्शाता है।

बच्चियों की हत्याएं और चुप्पी

जिस दिन (28 अगस्त 2025) प्रधानमंत्री

लेकिन उन्हें मुजफ्फरपुर की विभा कुमारी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की लाश पेड़ से लटकी मिली। उसकी मां कुछ ही दिन पहले इस दुनिया से विदा हो चुकी थी और पिता हैदराबाद में मजदूरी करता था। वह लड़की लकड़ी लेने घर से कुछ दूर महिनावाँ सोन बांध के पास गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। 27 अगस्त को पटना के ही गर्दनीबाग के अमलाटोला कन्या मध्य विद्यालय में पांचवीं कक्षा की छात्रा शौचालय में जली हुई मिली। यह भी बच्चियाँ किसी की बेटी, किसी की बहन थी। ये घटनाएं बिहार की राजधानी पटना में हुई, न कि किसी दूरदराज गांव में। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर एक शब्द तक नहीं बोला। अगर उन्हें 28 अगस्त को दरभंगा में दी गई गाली याद रही, तो 27 और 28 अगस्त को हुई इन बच्चियों की मौत वे कैसे भूल गये? 2 सितम्बर को प्रधानमंत्री जब भावुक होकर अपनी बात रख रहे थे, तब बिहार बीजेपी अध्यक्ष और वहां मौजूद कई महिलाओं की आंखों में आंसू दिख रहे थे। चार वर्षीय बेटी की लाश 2 सितम्बर को खेत से बरामद हुई? चार साल की बच्ची 1 सितम्बर को सुबह 10 बजे अपनी मां से कहकर निकली थी कि वह आंगनवाड़ी जा रही है, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी। उसके पिता मिंटू कुमार ने बताया कि शाम को पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन बच्ची की लाश अगले दिन ही घर से थोड़ी दूर मिली। प्रधानमंत्री जी, आपको गाली देने वाले शख्स को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बच्ची को 24 घंटे बाद सिर्फ लाश के रूप में खोजा जा सका। इन बच्चियों की आवाज न पुलिस-प्रशासन सुन पा रहा है, न ही जनप्रतिनिधि। इस तरह की दर्दनाक घटनाएं आए दिन हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री जी को गाली पर इमोशनल होने वाले पुरुष-महिला नेता इन क्रूर हत्याओं पर भी कभी आक्रोशित होंगे? इनके लिए बिहार या भारत बंद का ऐलान कब किया जाएगा?

चुनावी हथियार

13 नवम्बर 2022 को प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में कहा था- «लोग मुझसे पूछते है कि थकते नहीं हो? अब कल मैं सुबह दिल्ली में था, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर रात को आंध्र में, अभी तेलंगाना में। मैंने उनसे कहा कि रोज मैं ढाई-तीन किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने ऐसी रचना की है कि वे सारी गालियां मेरे भीतर जाकर न्यूट्रिशन में बदल जाती हैं। जब प्रधानमंत्री गालियों से ऊर्जा प्राप्त करने की बात कर चुके हैं, तो इस बार वही गालियां उन्हें ऊर्जाहीन कैसे कर गईं? वह कोई चुनावी सभा नहीं, बल्कि सरकारी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा- मैं जानता हूं कि इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। आज जब मैं बिहार की लाखों माताओं-बहनों के दर्शन कर रहा हूं, तो अपना दुख आपसे साझा कर रहा हूं... देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कि कुर्सी इन्हीं को मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता-जनार्दन ने एक गरीब मां के कामदार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधानसेवक बना दिया। प्रधानमंत्री ने सरकारी योजना के मंच से सत्ता और कुर्सी की बात छेड़कर साफ कर दिया कि असली मकसद बिहार चुनाव है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी महिला मोर्चा ने 4 सितम्बर को बिहार बंद का आह्वान भी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में यह भी कहा था- «जो लोग मेरे खिलाफ बोलने के लिए गालियों की डिक्शनरी प्रकाशित करते हैं। मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि ऐसे बयानों से दुखी या नाराज मत होइए। बस उनका मजा लीजिए, अच्छी चाय पीजिए और इस उम्मीद में सो जाइए कि अगले दिन कमल खिलेगा।» फिर इस बार प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को वही सलाह क्यों नहीं दी? उन्होंने सत्ता और कुर्सी के लिए मां की गाली को चुनावी हथियार क्यों बनाया? मां की गाली से आहत होकर बीजेपी वालों ने बिहार बंद के दौरान जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्ताव किया, वह मां (महिलाओं) का सम्मान नहीं बल्कि मां का अपमान दिखा। सड़क पर एक महिला शिक्षिका के साथ अभद्रता की गई, तो दूसरी ओर एक पत्रकार को फोटो लेने के हटने को कहने पर मां सूचक गाली दी गई। गर्भवती महिलाओं की एम्बुलेंस और स्कूली बच्चों की बस को भी रोका गया। साइकिल सवार के साथ धक्कामुक्की करने पर जब पत्रकार ने सवाल उठाया, तो सोनिया गांधी को बार डांसर कहा गया। महिलाओं के सम्मान के लिए उतरी बीजेपी खुद महिलाओं का ही अपमान कर रही थी। राजनीति में निजी भावनाओं का इस्तेमाल तभी जायज है जब वह सार्वजनिक हित में हो। जब यह केवल सत्ता को मजबूत करने का हथियार बन जाए, तब वह नैतिक पतन है। सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र में केवल बयानबाज़ी से अपमान का राजनीतिक लाभ उठाना, नैतिक जिम्मेदारी से बच निकलने का साधन बन गया है?

लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र में संवेदना का उपयोग यदि सिर्फ चुनावी लाभ के लिए किया जाए, तो न केवल भाषा का स्तर गिरता है, बल्कि राजनीतिक स्तर भी नष्ट हो जाता है। इसी कारण संसद से लेकर सड़क तक गाली-गलौच जैसे अपशब्द भाषा का प्रयोग आम हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के भी कई वक्तव्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 2 सितम्बर का भाषण राजनीतिक और भावनात्मक संवेदनाओं को चुनावी लाभ के लिए साधने का उदाहरण है। उन्होंने निजी चोटों को राष्ट्रीय विमर्श में बदलकर इसे परंपरा बना दिया है। इस परंपरा का नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है बेरोज़गारी, अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे गौण हो जाते हैं।

चुनाव आयोग की जल्दबाजी !

हमारे संविधान निर्माताओं ने जब स्वतन्त्र होने के बाद चुनाव आयोग को पूर्ण रूपेण स्वायत्तशासी व सरकार से निरपेक्ष दर्जा दिया था तो प्रत्येक भारतवासी को सत्ता में भागीदारी करने की गारंटी दी थी। क्योंकि लोकतन्त्र का मतलब ही जनता की पसन्द की अपनी सरकार होता है। चुनाव आयोग जनता की इसी इच्छा की पूर्ति कराता है और तय करता है कि हर भारतवासी की इसमें शिरकत हो। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हर मतदाता का वोट बनाने के लिए अभियान चलाया करता था और अपील करता था कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने जायें परन्तु पहली बार यह देखने में आ रहा है कि चुनाव आयोग खुद मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काट रहा है। वह नाम काटने का कारण भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही बताता है। ऐसा बिहार में हुआ है जहां 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गये हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने कहा कि वह विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। यह कार्य जब बिहार में शुरू किया गया तो इसका विरोध देश की विपक्षी पार्टियों ने किया और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का यह कार्य कानून को धता बता कर किया जा रहा है। इस बारे में देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी कई याचिकाएं दायर की गई जिन पर सुनवाई चल रही है और सबसे ताजा सुनवाई 8 सितम्बर को ही होनी है। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी वैध मतदाता के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड व खुद उसके द्वारा जारी किया गया वोटर कार्ड ऐसे दस्तावेज नहीं हैं जो उसके वैध भारतीय नागरिक होने के प्रमाण हों। अतः उसने 11 ऐसे दस्तावेजों को फेहरिस्त पकड़ा दी जिनकी जरूरत आम आदमी को मुसीबत के वक्त ही पड़ती है। इनमें जन्म प्रमाणपत्र से लेकर जाति प्रमाणपत्र व निवासी प्रमाणपत्र शामिल थे। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह आधार कार्ड को किसी भी नागरिक के वैध होने का सबूत समझे और अपने ही जारी किये गये वोटर कार्ड का भी संज्ञान ले। अब चुनाव आयोग पूरे भारत में बिहार की तर्ज का मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाना चाहता है जबकि सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका लम्बित है कि चुनाव आयोग क्या इस प्रकार का कोई अभियान चला सकता है। चुनाव आयोग को आखिरकार जल्दी किस बात की है? सवाल यह है कि चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम फैसले का इन्तजार क्यों नहीं करना चाहता? भारत का संविधान स्पष्ट रूप से जब यह कहता है कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की जांच केवल गृह मन्त्रालय ही कर सकता है तो चुनाव आयोग किस वजह से अपनी टांग इस क्षेत्र में अड़ाना चाहता है? चुनाव आयोग ने अभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक आगामी 10 सितम्बर को दिल्ली में बुलाई है। इस बैठक का मन्तव्य यह माना जा रहा है कि वह आगामी 1 जनवरी, 2026 से पूरे देश में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाना चाहता है। जाहिर है उसके इस कदम का विरोध देश के विपक्षी दल करेंगे क्योंकि वे कह रहे हैं कि इसके बहाने आयोग देश में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण का काम करना चाहता है। निश्चित रूप से यह कार्य चुनाव आयोग का नहीं है। उसे सिर्फ यह देखना होता है कि किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक का वोट बनने से न रह जाये। इसके अलावा उसका काम होता है कि पूरे देश में हर चुनाव पूरी तरह स्वतन्त्र तरीके से हों और मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग बिना किसी खौफ-ओ-खतर के करें। उनका वोट कोई भी उन्हें डरा कर या लालच देकर न ले सके। मगर चुनाव आयोग यदि नागरिकों की नागरिकता की जांच करने लगेगा तो इससे वह अपने लक्ष्य से भटक जायेगा और पूरे भारतीय समाज में बेवजह डर व्याप्त हो जायेगा। लोकतन्त्र में डर केवल कानून का ही होना चाहिए। जो लोग भारत के वैध नागरिक नहीं हैं और मतदाता बने हुए हैं उनमें कानून का डर होना चाहिए। मगर यह डर भारत के उस वैध नागरिक में नहीं होना चाहिए जिसके पास किसी कारणवश जन्म प्रमाणपत्र नहीं है। भारत की पुरानी पीढ़ियों में जन्म प्रमाणपत्र बनवाने की परंपरा ही नहीं थी और सारे कार्य उनकी वल्दियत के नाम पर ही होते थे। इस हकीकत को हमें स्वीकार करना चाहिए। नई पीढ़ियों में जन्म प्रमाणपत्र रखने की परम्परा जरूर पैदा हुई है जो कि देश में बढ़ती शिक्षा व्यवस्था की वजह से है। अब यदि राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की गरज से बुला रहा है तो यह उसकी जल्दबाजी होगी क्योंकि देश में इससे अगले वर्ष 2027 में जनगणना शुरू होनी है। जनगणना के दौरान नागरिकता की पहचान भी हो सकती है। इससे चुनाव आयोग का कार्य और सरल हो जाएगा। बिहार में जिस तरह 65 लाख मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग ने काटे हैं उससे पूरे देश में आशंका का वातावरण बना हुआ है जिससे लोगों का रोष चुनाव आयोग के प्रति पैदा हो सकता है। अभी तक चुनाव आयोग लोगों का मित्र ही समझा जाता है। उसकी छवि लोकमित्र जैसी है। अतः चुनाव आयोग को अपनी छवि की चिन्ता भी करनी चाहिए क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था है।

बुजुर्ग परिवार के बरगद पीपल की भांति

2021 में, पोप फ्रांसिस ने दादा-दादी और बुजुर्गों के लिए विश्व दिवस के रूप में विश्वव्यापी उत्सव की स्थापना की। दरअसल वह इस बात पर प्रकाश डालना चाहते थे कि बुजुर्ग हमारी दुनिया के लिए एक महान उपहार हैं, और हर पीढ़ी के पास देने के लिए कुछ न कुछ है। इस साल हमारे दादा-दादी और बुजुर्गों को याद करने के लिए निर्धारित इस दिन की चौथी वर्षगांठ होगी।हमारे दादा-दादी हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे हमारे परिवार के शीर्ष पर हैं। वे हमें मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करते हैं, और हममें से बहुतों के पास अपने दादा-दादी के साथ बीते समय की कहानियों और पारिवारिक अवसरों की प्यारी प्यारी यादें हैं। दादा-दादी दिवस हमें अपनी दादी और दादाओं का सम्मान करने का सही अवसर प्रदान करता है।दादा-दादी दिवस एक ऐसा दिन है जो परिवार के भीतर छोटे लोगों की शिक्षा और कल्याण के मामले में हमारे दादा-दादी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाने और उसे स्वीकार करने के लिए समर्पित है। यह हम सभी के लिए बुजुर्गों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता दिखाने, अपने दादा- दादी का सम्मान करने का एक आदर्श दिन है - वे जो कुछ भी करते हैं और जिसके लिए वे खड़े हैंयह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस तिथि को स्वीकार करें। दादा-दादी दिवस बच्चों के लिए यह जानने का एक बेहतरीन अवसर है कि दादा-दादी किस तरह से उनकी शिक्षा और भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। यह लोगों के लिए पुरानी पीढ़ियों से मिले मार्गदर्शन पर विचार करने और इसके लिए अपनी प्रशंसा दिखाने का एक बढ़िया समय हैइस तथ्य पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है कि दादा-दादी जब बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें अकेलापन महसूस हो सकता है, खासकर जब वे अकेले रहते हैं। यही कारण है कि अपने दादा-दादी को यह बताना महत्वपूर्ण है कि उन्हें कितना प्यार और सराहना मिलती है। बस अपने दादा-दादी से समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए संपर्क करना कि वे ठीक हैं, बहुत बड़ा अंतर लाने वाला है। हम जानते हैं कि जब भी कई विचार दिए गए हैं। इसमें कुछ अपने दादा-दादी की विरासत और इतिहास के बारे में सीखना या परिवार की परंपरा शामिल है। परिवार अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों की कहानियाँ सुनने के लिए एक साथ समय बिता सकते हैं और कुछ नर्सिंग होम में बुजुर्गों के साथ दिन का कुछ हिस्सा बिताने के लिए स्वेच्छा से आगे आ सकते हैं। आप अपने दादा-दादी को ग्रैंडपैरेंट्स डे पर खास महसूस कराने का प्रयास भी कर सकते हैं। क्यों न उन्हें फूलों का प्यारा गुलदस्ता देकर सरप्राइज दें? आखिर फूल किसे पसंद नहीं होते? किसी के लिए खूबसूरत फूलों की सजावट खरीदकर आप गलत नहीं हो सकते। दरवाजा खोलते ही फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता आपका इंतजार करता हुआ देखने से बेहतर कोई एहसास नहीं हो सकता। आप ताजे फूलों की जगह कृत्रिम फूलों पर विचार कर सकते हैं क्योंकि जब आप कृत्रिम फूलों का विकल्प चुनते हैं तो आप किसी को ऐसा तोहफा दे रहे होते हैं जो उनके लिए जीवन भर चलने वाला है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

कमल चौहान की हत्या से रही तनावपूर्ण स्थिति

मुरादाबाद। नशे के तस्करी को लेकर बढ़ती रंजिश में हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल चौहान की रविवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के दूसरे दिन डबल फाटक इलाके में तनाव बना हुआ है।

इलाके में तैनात की गई फोर्स

इलाके पुलिस ने भारी बल तैनात किया। नशे की तस्करी में बढ़ती रंजिश में हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल चौहान की दूसरे गुट ने गोलीमार हत्या कर दी। घटना के बाद दूसरे दिन डबल फाटक इलाके में तनाव बना हुआ है। हंगामे की आशंका के चलते पुलिस ने क्षेत्र में भारी बल तैनात कर दिया है। रविवार शाम करीब छह बजे कमल चौहान अपने पड़ोसी विशाल चौहान के साथ स्कूटी पर घर लौट रहे थे। जैसे ही वह करबला इलाके में पहुंचे वहां पहले से घात लगाए हिस्ट्रीशीटर सनी दिवाकर और उसके साथियों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद सीने व सिर में दो गोलियां मारकर हत्या कर दी। सोमवार दोपहर पुलिस ने कमल चौहान का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव को उनके घर लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्य आरोपियों की तलाश जारी है। कमल पर मादक पदार्थों की तस्करी समेत आठ मुकदमे दर्ज थे। फरवरी में उन्हें सवा किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसे 1× जून को जमानत पर रिहा किया गया था। जेल से लौटने के बाद उन्होंने चरस बिक्री फिर से शुरू कर दिया था।

पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए घोसी समाज ने बढ़ाये कदम

मुरादाबाद।

पंजाब प्रांत में आई भयंकर बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी है पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए मुरादाबाद से राहत सामग्री भेजे जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है स्वयंसेवी संगठन सहायता के लिए स्वयं आगे आकर हाथ बढ़ा कर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को ऑल इंडिया मुस्लिम घोसी चेरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एक ट्रक राहत सामग्री अपने स्तर से इकट्ठा की गई राहत सामग्री से भरे ट्रक को मंडलायुक्त की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अपर आयुक्त प्रथम सर्वेश कुमार गुप्ता एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष अली अहमद एडवोकेट व उनकी पूरी टीम की मौजूदगी में कमिश्नरी से पंजाब के लिए रवाना

किया गया। अपर आयुक्त प्रथम सर्वेश कुमार गुप्ता ने ट्रस्ट के इस सराहनीय कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा भी की और अन्य सामाजिक संगठनों से भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आने की जरूरत पर जोर दिया। बताया गया है कि राहत सामग्री से भरे ट्रक में दाल चावल घी तेल चीनी आदि रोजमर्रा की जरूरत की चीजे मौजूद है ट्रस्ट के मुख्य पदाधिकारी अली अहमद एडवोकेट ने बताया कि ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य खिदमते खल्क है और इस्लाम धर्म ने भी खिदमत खल्क को सबसे 'यादा अहमियत दी है इसी पैगाम को आम करते हुए उनके ट्रस्ट ने धर्म जाति से ऊपर उठकर घोसी समाज के साथ-साथ अन्य लोगों की मदद से राहत सामग्री इकट्ठा करके पंजाब के बाल पीढ़ियों तक पहुंचने का प्रयास किया है यदि जरूरत हुई तो और भी राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू के अलावा अली अहमद एडवोकेट मोहम्मद फहीम एडवोकेट मास्टर रईस अहमद मोहम्मद सलमान नावेद अखिलेश एडवोकेट अमन रफीक एडवोकेट एवं अजहर अली एडवोकेट आदि अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।

अपर आयुक्त प्रथम सर्वेश कुमार गुप्ता ने राहत सामग्री को कमिश्नरी से किया रवाना

हिन्दी दिवस समारोह की तैयार की रूपरेखा

मुरादाबाद।

हिन्दी साहित्य संगम की कार्यकारिणी की बैठक मिलन धर्मशाला, मिलन विहार, मुरादाबाद में आयोजित की गई। बैठक में हिन्दी दिवस समारोह की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में हिन्दी दिवस की पूर्व संध्या पर मुरादाबाद के वरिष्ठ साहित्यकार श्रीकृष्ण शुक्ल को हिन्दी साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष श्री रामदत्त द्विवेदी जी ने की तथा सचालन महासचिव जितेन्द्र कुमार जौली ने किया। बैठक में योगेन्द्र वर्मा व्योम, चिरंजीलाल चंचल, नकुल त्यागी, राजीव प्रखर, रवि चतुर्वेदी, डॉ0 मनोज रस्तोगी, रामदत्त द्विवेदी, जितेन्द्र कुमार जौली आदि लोग उपस्थित रहे।

टीटीएयूपी ट्रैवल मार्ट टीटीएम 2025 का लखनऊ में सफलतापूर्वक समापन

लखनऊ ।

होटल हयात रीजेंसी, लखनऊ में ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश (TTM) द्वारा आयोजित 8वां ट्रैवल मार्ट (TTM 2025) सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष विवेक पांडेय, पूर्व उपाध्यक्ष एस.एम.ए. शीराज़, वर्तमान अध्यक्ष एम. आज़म, उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा, सचिव संदीप श्रीवास्तव, तथा कोर टीम के सदस्य अर्शद ज़ैदी, गायत्री खन्ना, मेराज ज़ैदी और आकाश खन्ना उपस्थित रहे। TTM 2025 में इस वर्ष 45 प्रदर्शकों और 315 पंजीकृत खरीदारों ने भाग लिया, जिनमें लखनऊ सहित 26 से अधिक शहरों के प्रतिनिधि शामिल थे। इनमें से 70 खरीदार पूर्ण रूप से आमंत्रित (होस्टेड) थे, जबकि शेष आंशिक रूप से आमंत्रित (सेमी-होस्टेड) थे। आयोजन के दौरान 7,000 से अधिक पूर्व-निर्धारित बी2बी बैठकें (BwB Meetings) आयोजित की गईं, जिससे प्रमुख डीएमसी, एयरलाइंस, होटल ब्रांड्स, पर्यटन बोर्ड्स एवं उभरते उद्यमियों के लिए एक सशक्त नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध हुआ। टीटीएयूपी प्रतिनिधियों ने कहा कि, TTM 2025 केवल एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि यह व्यापार,

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया शुभारंभ
45 प्रदर्शक और 315 खरीदार हुए शामिल

सहयोग और विकास को नई दिशा देने वाला मंच है, जो उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन परिदृश्य पर और मज़बूती से स्थापित करता है।

रोटरी क्लब के सदस्यों के प्रथम गुरु का किया सम्मान

मुरादाबाद। रोटरी क्लब मुरादाबाद एक्सिस द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार क्लासिक बैंकट हॉल दिल्ली रोड मुरादाबाद पर आयोजित प्रथम गुरु सम्मान समारोह में क्लब सदस्यों के प्रथम गुरु का सम्मान स्मृति चिन्ह व उपहार भेंट कर एवं अंग वस्त्र पहनाकर किया। रोटेरियन सागर राय, रोटेरियन गोविंद गुप्ता व रोटेरियन राहुल अग्रवाल के प्रथम गुरु के रूप में जीवन की प्रथम गुरु उनकी माता क्रमशः सरिता राय, माधुरी देवी व नीतू अग्रवाल को; रोटेरियन अनूप गुप्ता, रोटेरियन गुरजीत सिंह व रोटेरियन डॉ विवेक गोयल के प्रथम गुरु के रूप में जीवन के उतार-चढ़ाव व संघर्षों का सामना करने में सक्षम बनने की प्रेरणा देने वाले उनके स्वर्गीय पिता क्रमशः प्रोफेसर विजय गुप्ता, सतेंद्र पाल सिंह व डॉ अनिल कुमार गोयल को; रोटेरियन गुरप्रीत सिंह को औपचारिक शिक्षा प्रदाता गुरु शिशिर गुप्ता एडवोकेट को; रोटेरियन मुकुल अग्रवाल को वैधानिक संरक्षण व मार्गदर्शन प्रदाता गुरु के रूप में पीके गोस्वामी एडवोकेट को; समाजसेवी रोटेरियन विवेक गोयल

को सामाजिक दायित्वों से परिचित कराने व समाजसेवी जीवन चुनने हेतु प्रेरित करने वाले गुरु के रूप में गोकुलदास को; रोटेरियन अरुण प्रकाश गुप्ता को व्यवसाय के आरंभिक काल में व्यवसाय से विमुख होने से रोकने वाले तथा उन्हें उनके व्यवसाय में शिखर तक पहुंचाने वाले व्यावसायिक गुरु के रूप में सुनील कुमार गुप्ता को; तो रोटेरियन संजय सिंघल, रोटेरियन शुभम अग्रवाल, रोटेरियन रुचित अग्रवाल व रोटेरियन नेहा सिंघल को अध्यात्म से जोड़े रखने वाले आध्यात्मिक गुरु के रूप में राजेंद्र पाल गुप्ता को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष रोटेरियन रश्मि गोयल ने बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर क्लब द्वारा मात्र औपचारिक शिक्षा प्रदाता गुरुओं का सम्मान न करके क्लब सदस्यों के उन गुरुओं का सम्मान किया गया है जिन्हें वे अपना प्रथम गुरु मानते हैं। मुख्य अतिथि नामित मंडलाध्यक्ष रोटेरियन काव्य सौरभ रस्तोगी ने कहा क्लब द्वारा इस प्रकार की सभा का आयोजन अभूतपूर्व है। उन्होंने क्लब अध्यक्ष, सचिव व संयोजक को इस प्रकार की संकल्पना के लिए साधुवाद दिया।

चोर गिरफ्तार

कप्तानगंज(कुशीनगर)। थाना क्षेत्र के मथौली बाजार में विगत दिनों हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए मुकामी पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से नगदी समेत गहने बरामद किया है।दोनों आरोपियों के खिलाप विधिक कार्यवाही की जा रही है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र बोदरवार निवासी सिप्पी साहनी पुत्र बेचू व आकाश पुत्र सुरेश को मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार कर इनके पास से चोरी के मंगलसूत्र, अंगूठी, झुमका, पायल समेत नगदी बरामद करते हुए पूर्व में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 392/ धारा 305(ए), 331(4), 317 (2) बीएनएस अंतर्गत कार्यवाही में जुटी है। इस कार्यवाही में एसओ चन्द्र भूषण प्रजापति प्रमोद कुमार अंजनी कुमार शुभम सिंह अजय यादव आदि शामिल रहे।

सक्षम काशी प्रान्त के प्रशिक्षण वर्ग का हुआ आयोजन

बक्शा, जौनपुर।

स्थानीय क्षेत्र में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में सक्षम काशी प्रान्त प्रशिक्षण वर्ग का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ जिसका शुभारम्भ दीप प्रज्वलन से हुआ जहां सभी विशिष्ट अतिथियों ने संयुक्त रूप से सहभागिता किया। कार्यक्रम का उद्घाटन सुरेश जी राष्ट्रीय महासचिव सक्षम, रामचंद्र जी प्रान्त प्रचारक प्रमुख एवं वेंकट जी राष्ट्रीय प्रभारी दिव्यांग जन सेवा केंद्र ने किया। संचालन की जिम्मेदारी प्रयाग दत्त जी काशी प्रांत सह सचिव ने निभाई। इस मौके पर प्रान्त प्रचारक प्रमुख रामचन्द्र जी ने संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर 5 महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण वर्ग में 12 जिलों से आये सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सत्र में लगभग 200 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में पुष्पराज जी जिलाध्यक्ष भाजपा, डॉ. सुभाष जी जिला संचालक सेवा भारती, अनिल जी जिलाध्यक्ष सेवा भारती, डॉ. सुरेश कनौजिया निदेशक कृषि विज्ञान केंद्र बक्शा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। समापन सत्र का उद्बोधन बांके लाल जी क्षेत्र गौ सेवा प्रमुख ने जबकि धन्यवाद ज्ञापन डा. उत्तम गुप्ता जिलाध्यक्ष सक्षम ने प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर घनश्याम पाण्डेय प्रान्त सचिव, डा. सुधाकर दुबे सक्षम प्रमुख मछलीशहर तहसील, रोहित जी विभाग मंत्री सेवा भारती, विक्रांत जी, ज्ञान चंद्र जी, उर्वशी जी, राखी जी, अनुराधा जी, बिट्टू दीदी, मीणा जी, डॉ. साधना, डॉ. मंगल सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। यह प्रशिक्षण वर्ग दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं संगठनात्मक विकास की दृष्टि से अत्यन्त सफल और प्रेरणादायी सिद्ध हुआ।

इनरव्हील क्लब जौनपुर ने गुरूजनों को किया सम्मानित

जौनपुर। शिक्षक दिवस पर इनरव्हील क्लब ऑफ जौनपुर सिराज-ए-हिन्द भावपूर्ण शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में समाज को दिशा देने वाले शिक्षकों के अमूल्य योगदान को सम्मानित किया गया। क्लब की ओर से शिक्षकों को उनकी निःस्वार्थ सेवा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र शॉल भेंट किये गये। इस दौरान उपस्थित सभी सदस्यों ने शिक्षकों को ज्ञान और संस्कारों का सच्चा मार्गदर्शक बताते हुए उनके योगदान की सराहना किया। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि एक शिक्षक आशा जगाता है, कल्पना को साकार करवाता है और जीवन भर सीखने का भाव उत्पन्न करता है। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष शोभा सिंह सहित सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

ग्रेट निकोबार परियोजना सुनियोजित दुस्साहस और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ विश्वासघातः सोनिया गांधी

नई दिल्ली । कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि ग्रेट निकोबार परियोजना एक सुनियोजित दुस्साहस, न्याय का उपहास और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ विश्वासघात है,जिसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। सोनिया गांधी ने अंग्रेजी दैनिक द हिंदू के लिए लिखे एक लेख में यह भी कहा कि जब कुछ जनजातियों का अस्तित्व ही दांव पर हो, तो देश की सामूहिक अंतरात्मा चुप नहीं रह सकती और न ही चुप रहनी चाहिए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने लेख में कहा, पिछले 11 वर्षों में अंधेरी और गलत नीतियों का निर्माण हुआ है। इस सुनियोजित दुस्साहस की श्रृंखला में नवीनतम है ग्रेट निकोबार मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना। 272,000 करोड़ रुपये का यह पूरी तरह से गलत खर्च द्वीप के मूल आदिवासी समुदायों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करता है, दुनिया के सबसे अनोखे वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक के लिए खतरा है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद इसे असंवेदनशीलता से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे सभी कानूनी और सुविचारित प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि इस परियोजना के माध्यम से आदिवासियों को दरकिनार जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, '' ग्रेट निकोबार द्वीप दो मूल समुदायों, निकोबारी जनजाति और शोम्पेन जनजाति (एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह) का घर है। निकोबारी आदिवासियों के पैतृक गांव परियोजना के प्रस्तावित भू-क्षेत्र में आते हैं। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के दौरान निकोबारी लोगों को अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सोनिया गांधी के अनुसार, यह परियोजना अब इस समुदाय को स्थायी रूप से विस्थापित कर देगी जिससे उनके अपने पैतृक गांवों में लौटने का सपना टूट जाएगा। उनका दावा है कि शोम्पेन समुदाय को और भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। सोनिया गांधी ने कहा, शोम्पेन समुदाय को एक और भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। द्वीप की शोम्पेन नीति, जिसे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, विशेष रूप से अधिकारियों से यह अपेक्षा करती है कि वे बड़े पैमाने पर विकास प्रस्तावों पर विचार करते समय इस जनजाति की भलाई और अखंडता को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि इसके बजाय यह परियोजना शोम्पेन जनजातीय अभयारण्य के एक बड़े हिस्से को अधिसूचित नहीं करती, शोम्पेन के निवास वाले वन पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करती है और द्वीप पर बड़े पैमाने पर लोगों और पर्यटकों की आमद का कारण बनेगी। उन्होंने कहा, अंततः शोम्पेन खुद को अपनी पैतृक भूमि से कटा हुआ पाएंगे और अपने सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व को बनाए रखने में असमर्थ पाएंगे। फिर भी, सरकार हठधर्मिता और हैरान करने वाली जिद पर अड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय समुदायों की सुरक्षा के लिए स्थापित उचित प्रक्रिया और नियामक सुरक्षा उपायों की अवहेलना की गई है। सोनिया गांधी ने कहा, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार किए गए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) में निकोबारी और शोम्पेन को इस प्रक्रिया के हितधारक के रूप में मान्य जाना चाहिए था .

कुलगाम में भीषण मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने मार गिराए दो आतंकी

दो सैनिक बलिदान होने की सूचना

कुलगाम। दक्षिण कश्मीर में जिला कुलगाम के अंतर्गत गड़ार में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मिली जानकारी के अनुसार यहां तीन आतंकियों के फंसे होने की सूचना के बाद मुठभेड़ शुरू हुई थी। जिसमें से अब तक दो आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। सुरक्षाबल आतंकियों को घेरकर गोलीबारी कर रहे हैं। जारी मुठभेड़ में दो सैनिकों के भी बलिदान होने की सूचना है। हालांकि, अब तक इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल जम्मू-कश्मीर का विशेष अभियान समूह, सेना और सीआरपीएफ मौके पर मौजूद है। एक्स पर शेयर किए गए ट्वीट में कश्मीर जोनल पुलिस ने कहा कि एक विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर मुठभेड़ शुरू हुई। ट्वीट में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया है कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कुलगाम के गुद्दर जंगल में मुठभेड़ शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की विशेष अभियान समूह (एसओजी) कम्प पर है।

नेपाल में सोशल मीडिया बैन

सड़क पर युवाओं का बवाल, संसद भवन में भी घुसे; पुलिस फायरिंग में 19 की मौत, 200 घायल

काठमांडू ।

नेपाल में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान 19 लोगों की मौत हो गई है। ANI के मुताबिक नेपाल पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। 200 से ज्यादा युवा घायल भी हुए हैं। इस प्रदर्शन की अगुआई Gen-Z यानी 18 से 30 साल के युवा कर रहे हैं।12 हजार से ज्यादा युवा प्रदर्शनकारी सोमवार सुबह संसद भवन परिसर में घुस गए थे, जिसके बाद सेना को कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का यह पहला मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वाले को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से सात दिन की समय सीमा दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई।

मथुरा-वृंदावन में यमुना मचा रही तबाही...बांके बिहारी मंदिर मार्ग हुआ जलमग्न, अयोध्या नगर में गिर गया मकान

मथुरा । यमुना का जलस्तर बढ़ने से मथुरा और वृंदावन में घर डूबते जा रहे हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर मार्ग पर पानी पहुंच गया है। वहीं मथुरा के अयोध्या नगर में हुए जलभराव से एक मकान गिर गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में परिवार के लोग बाल-बाल बच गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बांकेबिहारी मंदिर जाने वाले मार्ग में भी यमुना का पानी पहुंच गया है। दाऊजी तिराहे तक सड़कें जलमग्न हो गई हैं। इस वजह से यहां के दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं मथुरा के लक्ष्मी नगर के अयोध्या नगर में रविवार को बाढ़ का पानी भरने से एक मकान गिर गया। घर में मौजूद लोगों ने जैसे-तैसे भाग कर अपनी जान बचाई। पीड़िता का कहना है कि रविवार रात को उनके मकान के चारों ओर पानी भर गया। इसके बाद उनके मकान की दीवार दरकने लगीं और फर्श भी धंसने लगे। फिर थोड़ी देर बाद मकान के पिछले हिस्से की दीवार गिर गई और दोनों कमरे धराशाई हो गए।

एक मंजिल तक भरा पानी

लक्ष्मी नगर के ईसापुर में एक मंजिल तक पानी भरने के बाद बाढ़ प्रभावित लोग रेलवे ट्रैक को पार करके सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। सोमवार दोपहर 1:00 बजे दर्जनों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे थे, इसी दौरान हावड़ा की तरफ से तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। लोगों ने जैसे तैसे रेलवे ट्रैक से भाग कर अपनी अपनी जान बचाई। वहीं रेलवे ट्रैक के पास एसडीएम महावन कुर्सी पर बैठी रहीं। उन्होंने न लोगों को रोका और न ही खुद वहां से हटीं। लोगों ने तेज आवाज से चिल्लाना शुरू किया, इसके बाद सब तितर बितर हुए।

नासिक में एमएसआरटीसी बस और मोटरसाइकिल की टक्कर, तीन लोगों की मौत

नासिक । महाराष्ट्र के नासिक जिले में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बस और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, नासिक जिले के भंजरपाड़ा फाटा के पास एक बस अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गई। मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सटाना पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह 11 बजे ताहराबाद-सटाना मार्ग पर वनोली गांव के पास भंजरपाड़ा फाटा पर हुई। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान गोविंदा कालू पवार, विकास जयराम माली और रोशन दयाराम माली के रूप में हुई है, जो सभी सुकतमन गांव के

सीएम नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं-सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राय में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। कुमार ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार लाने में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनको इसी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देते हुए मानदेय में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय का फायदा राय के 1.14 लाख आंगनबाड़ी सेविकाओं-सहायिकाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बनने के बाद से ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन उपायों के क्रियान्वयन में आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका को सरकार ने सराहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय में बढ़ोतरी के फैसले से आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मनोबल और ऊंचा होगा तथा समेकित बाल विकास सेवाएं और प्रभावी ढंग से लागू की जा सकेंगी। उल्लेखनीय है कि राय में 1.20 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका हैं जिन्हें मानदेय में इस बढ़ोतरी से लाभ होगा।

नीतीश-मोदी सरकार पर तेजस्वी का वार- 20 साल में बिहार क्यों बना बेरोजगारी-पलायन का गढ़?

पटना।

बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही, राय के पूर्व उपमंत्री और पूर्व राजद विधायक तेजस्वी यादव ने सोमवार को दावा किया कि एनडीए सरकार ने बिहार को बेरोजगारी, पलायन और गरीबों का केंद्र बना दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 20 साल और केंद्र में 11 साल से नीतीश-मोदी सरकार के सत्ता में रहने के बावजूद, एनडीए सरकार ने बिहार को बेरोजगारी, पलायन और गरीबों का मुख्य केंद्र बना दिया है। यह मेरा दावा नहीं है, बल्कि भारत सरकार की नीति आयोग की रिपोर्टें साल-दर-साल यही कहती आ रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार को प्रति व्यक्ति आय दुनिया के सबसे गरीब अफ्रीकी देशों, युगांडा और स्वाजीलैंड से भी कम रही है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे ने अपने पोस्ट के माध्यम से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों है? और पिछले 20 वर्षों में बिहार से कितना पलायन हुआ है, और बिहार में पलायन अभूतपूर्व दर से क्यों बढ़ रहा है? इसके अलावा, तेजस्वी यादव ने पूछा कि सरकार ने 20 सालों में राय में क्षेत्र-विशिष्ट क्लस्टर क्यों नहीं बनाए। उन्होंने यह भी पूछा कि राय में कितनी मिलें, कुल कितने उद्योग और कारखाने बंद हुए हैं। इसके अलावा, उन्होंने पिछले 20 सालों में परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर भी सरकार से सवाल किया।

उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीआरएस-बीजद का बड़ा एलान; मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे दोनों दल

नई दिल्ली । आज देश के नए उपराष्ट्रपति के नाम का एलान हो जाएगा। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी सी. पी. राधाकृष्णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। इस बीच, दो राजनीतिक दलों ने कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का एलान किया है। इन दलों में बीआरएस और बीजू जनता दल शामिल है। बता दें कि जगदीप धनखड़ के अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण रिक्त हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए मध्यावधि चुनाव कराया जा रहा है। आज कल यानी नौ सितंबर को यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से ठीक एक दिन पहले बीआरएस और बीजू जनता दल ने चौंकाने वाला एलान किया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी राम राव ने कहा कि उनकी पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी। इसी तरह बीजद ने भी ऐसी ही घोषणा की है। बीजद के नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि बीजू जनता दल मंगलवार को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के बीच सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन दोनों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। यह एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच एक तरह से शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। बीजद और बीआरएस के चुनाव से हटने के बाद भी अभी तक अकाली दल, जेडीएस और वीओटीटीपी के एक-एक सांसद और तीन निर्दलीय सांसदों ने अभी तक अपनी पसंद का स्पष्ट संकेत नहीं दिया है।

29 महीने बाद भी 3 घंटे! जयराम रमेश बोले- पीएम का मणिपुर दौरा असंवेदनशीलता की हद

नई दिल्ली ।

कांग्रेस महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 सितंबर को प्रस्तावित मणिपुर यात्रा की आलोचना करते हुए इसे राय के लोगों का अपमान बताया। एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस सांसद ने यात्रा की तैयारियों के बारे में एक अखबार की कटिंग साझा की और कहा कि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर में केवल तीन घंटे ही बिताएँगे। जयराम रमेश ने लिखा कि प्रधानमंत्री को 13 सितंबर को प्रस्तावित मणिपुर यात्रा का उनके समर्थक स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वह राय में लगभग 3 घंटे ही बिताएँगे - जी हाँ, सिर्फ 3 घंटे। इतनी जल्दबाजी में की गई यात्रा से वह क्या हासिल करना चाहते हैं? जयराम रमेश ने आगे कहा कि यह वास्तव में राज्य के लोगों का अपमान है, जिन्होंने 29 लंबे और कष्टदायक महीनों तक उनका इंतजार किया है। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री वास्तव में मणिपुर नहीं आएँगे, जिन्होंने एक बार फिर मणिपुर के लोगों के प्रति अपनी उदासीनता और असंवेदनशीलता प्रदर्शित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 13 तारीख को कुछ घंटों के लिए मणिपुर पहुँचेंगे और दो स्थानों पर जनसभाएँ करेंगे। प्रधानमंत्री की राय यात्रा पर चर्चा के लिए आज इम्फाल के राजभवन में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने की और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष सत्यव्रत, विधायक और मणिपुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अधिकारीमायुम सारदा देवी ने भाग लिया। बैठक के दौरान, राज्य की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित की जाने वाली जनसभाओं और प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की जाने वाली परियोजनाओं पर चर्चा की गई।

किस तरह के जज हैं आप? लालू से मुलाकात पर रविशंकर प्रसाद का सुदर्शन रेड्डी पर हमला

नई दिल्ली । भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी द्वारा चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, भाजपा सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हैं। हम आज भी न्यायाधीशों का बहुत सम्मान करते हैं, चाहे वे वर्तमान में कार्यरत हों या सेवानिवृत्त। लेकिन जब कोई न्यायाधीश चुनाव में खड़ा होकर कुछ बड़ी बातें कहता है, तो सवाल जरूर उठेंगे। रेड्डी के एक अखबार के लेख की ओर इशारा करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था, देश की आत्मा बचाने के लिए मुझे वोट दें विपक्षी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, प्रसाद ने कहा कि रेड्डी ने इस लेख में देश को बचाने के लिए कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने

लोकतंत्र के मंदिर और अंतरात्मा की बात की। सुदर्शन रेड्डी ने बयान दिया है कि देश की आत्मा बचाने के लिए मुझे वोट दें। लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए रेड्डी पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा, आप सुप्रीम कोर्ट के किस तरह के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो घोटाले का दोषी है? और लालू प्रसाद तो मतदाता भी नहीं हैं और न ही सांसद, फिर आप राष्ट्र की आत्मा की प्रशंसा करने की बात क्यों कर रहे हैं? यह पाखंड है! कृपया राष्ट्र की आत्मा की बात न करें। उन्होंने आगे कहा कि यह घोर पाखंड है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। यह निंदा के योग्य है। इससे पहले, भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए रेड्डी की आलोचना की। उन्होंने इस मुलाकात को किसी उच्च संवैधानिक पद के आकांक्षी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान बताया। इससे पहले आज, भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए रेड्डी की आलोचना की। उन्होंने इस मुलाकात को एक उच्च संवैधानिक पद के आकांक्षी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान बताया।

आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं

एसआईआर पर सुनवाई | सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा- इसे 12वां दस्तावेज माना जाए

नई दिल्ली ।

बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि एसआईआर में पहचान के उद्देश्य से आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाए. मतदाता सूची में किसी मतदाता को शामिल/बहिष्कृत करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को भी ध्यान में रखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता की पहचान के लिए आधार को दस्तावेज मानने पर विचार करने को कहा. इसने स्पष्ट किया कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है. चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान कहा, 7.24 करोड़ में से 99.6 प्रतिशत ने पहले ही दस्तावेज जमा कर दिए हैं. पिछले आदेश में 65 लाख लोगों के लिए आधार को अनुमति दी गई थी. अब उनके लिए किसी भी याचिकाकर्ता ने यह नहीं बताया है कि बड़ी संख्या में लोगों को गलत तरीके से बाहर रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अकेले आधार को भी 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर माना जाए. कोर्ट ने कहा कि आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है (कि आधार सही या नहीं). जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम साफ कर दे रहे हैं कि

आधार सिर्फ निवास के प्रमाण के लिए है न कि नागरिकता तय करने के लिए.

अवैध प्रवासियों को अनुमति देने के लिए नहीं कह रहे

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कोई भी अवैध प्रवासियों को अनुमति देने के लिए नहीं कह रहा है. हम जानते हैं कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं. मान लीजिए कि यह बारहवां दस्तावेज है तो इसमें क्या समस्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संशोधित मतदाता सूची प्रक्रिया में शामिल या बहिष्कृत लोगों की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार अधिनियम 2016 के तहत जारी आधार कार्ड को स्वीकार किया जाएगा और इसे 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा. हालांकि अधिकारी प्रस्तुत किए गए कार्ड की प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकते हैं और आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा.

99.6फीसदी ने पहले ही दस्तावेज जमा कर दिए

इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने कहा, पैरा लीगल वालंटियर की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई. चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि वे अवैध प्रवासियों के लिए ऐसा चाहते हैं. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई नहीं चाहता कि अवैध प्रवासी मतदाता सूची में शामिल हों. चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार के 99.6 प्रतिशत नागरिकों ने पहले ही 11 सूचीबद्ध दस्तावेजों में से एक पेश किया है. चुनाव आयोग के अनुसार, 7.24 करोड़ में से 99.6 प्रतिशत ने पहले ही दस्तावेज जमा कर दिए हैं. पिछले आदेश में 65 लाख लोगों के लिए आधार की अनुमति दी गई थी. अब उनके लिए किसी भी याचिकाकर्ता ने यह नहीं बताया है कि बड़ी संख्या में लोगों को गलत तरीके से बाहर रखा गया है.

-: सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी :-

आपदा पीड़ितों को दी 10 करोड़ की मदद; राहत सामग्री के ट्रकों को दिखाई हरी झंडी

सहारनपुर ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को सहारनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने आपदा प्रभावित राज्यों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पांच-पांच करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए तथा हल्द्वानी से उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लखनऊ ही नहीं, बल्कि पूरा सहारनपुर भी आपदा पीड़ितों के साथ खड़ा है। सीएम योगी ने जिले में आई आपदा से हुए नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि जल्द ही प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा।